(ख) उपरोक्त में से कितने आवासों में लाभार्थी बस गए हैं और कितने आवास अभी भी खाली पड़े हैं; और

(ग) इस योजना पर इसके प्रारम्भ होने से लेकर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) चल रही आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक निर्मित आवासों की संख्या 1920899 है।

(ख) योजना आयोग द्वारा कराये गए अध्ययनों के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 86 प्रतिशत से भी अधिक आवासों का कब्जा ले लिया गया और उनमें लोग रह रहे थे तथा उन परिवारों के लगभग 84 प्रतिशत ने उनके आबंटित किये गए आवासों के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया। कुछ मामलों में, लाभार्थियों ने आवासों को कब्जे में नहीं लिया क्योंकि आवास मुख्य बसावट अथवा कार्य-स्थल से काफी दूर थे। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गए कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास गांव के समीप हों और अधिक दूरी पर न हों ताकि रक्षा एवं सुरक्षा, कार्यस्थल की समीपता तथा समाज के बीच उनकी सम्पर्कता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) 1985-86 में इन्दिरा आवास योजना के शुरू होने से लेकर अब तक, 3771.47 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया गया है जिससे 3015964 आवासों को बनाया गया है।

दिल्ली गोल्फ क्लब के पट्टे का नवीनीकरण

2511. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री संजय डालमिया:

क्या **प्रधान मंत्री** 12 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2590 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली गोल्फ क्लब को दी गई भूमि के संबंध में पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि को और किस अवधि तक नवीकृत किया गया है;

(ग) क्या गोल्फ क्लब द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह भुगतान कब किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेश्वरलू): (क) जी; हां।

(ख) दिनांक 1.1.1991 से 31.12.2010 तक के लिए पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्लब ने विचाराधीन अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क अदा कर दिया है।

पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2512. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमोत्तर क्षेत्र, विशेषकर गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना में मुख्य कठिनाइयां क्या-क्या हैं;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में ऐसे और अधिक उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ङ) गुजरात में स्थापित किए जाने वाले अधिक संभावना वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1992-93) के अनुसार गुजरात राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 1,178 फैक्ट्रियां थी। खाद्य व्यापार और उद्योग महासंघ की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में अधिक लागत के कारण सीमित बाजार; कर और शुल्क; सुदृढ़ बागवानी आधार की कमी; तकनीकी जनशक्ति की कमी के बीच तालमेल की कमी; बुनियादी समर्थन का अभाव तकनीकी जनशक्ति की कमी आदि जैसी कठिनाइयां उद्योग के

सामने है। सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है और शुल्क तथा करों को कम किया है तथा बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। मंत्रालय स्वंय किसी राज्य मे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार आधुनिकी-करण के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

Misutilization of Indira Awas Yojana Funds

2513. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the steps being taken by Government to reduce corruption and misutilisation of funds meant for Indira Awas Yojana being implemented in different parts of the country;

(b) whether Government have issued any directions to the State Government in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (c) The Indira Awas Yojana is being implemented through the District Rural Development Agencies (DRDAs)/Zila Parishads as per the guidelines provided under the scheme. The funds under the scheme are provided directly to DRDAs/Zila Parishads and the scheme is being implemented by the Panchayat Samiti/Block Development Officer. From time to time the Government is issuing instructions/directions to the State Governments for smooth and effective implementation of the scheme. Any specific complaint/representation with regard to misutilisation of funds is properly looked into for taking appropriate action in the matter.

Guidelines for Power Purchase Agreements

2514. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the guidelines in respect of Power Purchase Agreements (PPA);

(b) the number and details of Power Purchase Agreements signed during the last three years; and

(c) what steps Government have taken to enforce the said Agreements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) The power purchase agreement (PPA) is a contract between the State Electricity Boards (SEBs) and the independent power producers (IPPs) in which the modalities for purchase/sale of power are negotiated between the two parties. As such the issue of monitoring of PPAs comes under the purview of the respective State Governments. Normally the Government of India does not monitor the progress in finalisation of these agreements. To assist the State Government/SEBs in formulation of these agreements, Government of India circulated guidelines in respect of PPAs in 1994. The Ministry of Power also circulated a draft model PPA to enable the State Governments to formulate their own PPAs and also organised training workshops on PPAs. As per the information available in the Ministry of Power, 23 PPAs have been signed by SEBs.

Major Housing Schemes of D.D.A.

2515. SHRI G. PRATHPA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the major housing schemes under implementation by DDA;

(b) whether any targets have been fixed by the DDA to provide housing to the needy;